Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 51 , 15 नवम्बर, बुधवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480 4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

महिलाओं, दोपहिया वाहनों को छूट दे एनजीटी : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में सोमवार को पुर्नविचार याचिका देकर आड इवन पग्राली लागू करने पर इससे दो पहिया वाहनों के साथ महिलाओं को भी छूट देने की मांग की। दिल्ली सरकार ने इन दो कैटगरी को छूट के साथ आड इवन लागू करने की घोषणा पिछले सप्ताह की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल की मनाही के बाद आड इवन नहीं लागू किया गया। अब दिल्ली सरकार ने पुर्नविचार याचिका दायर की है। यानि महिला व दोपहिया वाहनों को छूट मिलने के बाद ही आड ईवन योजना लागू करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया था कि पर्याप्त संख्या में बसों का अभाव है। यादि दोपहिया वाहन को छूट न मिलने से बड़ी संख्या में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

शिया वक्फबोर्ड ने कहा- श्री राम की नगरी है अयोध्या, मंदिर वहीं बनना चाहिए

इलाहाबाद। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और दोनों समुदाय के लोगों को आपसी सहमित से इस धार्मिक नगरी में राम मंदिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। रिजवी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि से अल्लापुर स्थित बाघम्बरी गद्दी मठ में ये बाते कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। सोमवार को वसीम रिजवी पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि दोनों समुदाय के लोगों को धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत कर अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद निपटाने का प्रयास करना चाहिए। भारत विश्व में एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही रिजवी ने कहा, 'धर्म के नाम पर यहां राजनीति कर अब देश की अखंडता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे बचाने के लिए यह पहल जरूरी है।' वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही मसौदा तैयार कर दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर से गिरकर महिला यात्री घायल

नई दिल्ली। इंडिगो की एक महिला यात्री को एयरलाइन के कर्मचारी द्वारा व्हीलचेयर पर ले जाते समय उसके गिरने की घटना को भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने बड़ी लापरवाही बताया है। लखनऊ हवाई अड्डे पर हुई इस घटना को लेकर एएआई और एयरलाइंस के बीच विवाद छिड़ गया है।यह घटना शनिवार को रात आठ बजे हुई। इंडिगो का दावा है कि हवाई अड्डे पर जमीन में चटक की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं एएआई का कहना है कि इंडिगो के कर्मचारी की गंभीर लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना हुई। एक बयान में इंडिगो के प्रवक्ता ने यात्री उर्वशी पारीख वीरेन के साथ हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी है। इस मामले से पहले इंडिगो हवाई सेवा एक यात्री के साथ बदसलूकी करने के मामले में सुर्खियों में आई थी और इसके लिए एयरलाइंस ने माफी मांगी थी। ताजा घटना पर इंडिगो प्रवक्ता ने कहा कि इंडिगो यात्री को आगंतुक कक्ष की ओर व्हीलचेयर से ले जाया जा रहा था। जब कर्मचारी गाड़ियों की लेन से गुजर रहा था तभी फर्श पर दरार की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और महिला व्हीलचेयर से नीचे गिर गई। गिरने से यात्री घायल हो गई। उसे तुरंत एएआई के डाक्टर के पास ले जाया गया और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई।वहीं लखनऊ हवाईअड्डे का परिचालन करने वाली एएआई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण इंडिगो के कर्मचारी की लापरवाही है क्योंकि उसने पक्की सड़क पर गलत रास्ते को चुना।

शादी का झांसा देकर पुलिस इंस्पेक्टर ने किया महिला के साथ रेप

इलाहाबाद। शाहगंज थाने में तैनात एक दरोगा के खिलाफ करेली की महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक फ्तेहपुर तबादला होने के बाद दरोगा ने महिला से दूरी बना ली थी। सोमवार को पीड़िता ने दरोगा का वीडियो और फोटो दिखाकर इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर करेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। करेली की एक महिला प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। 2008 में उसका किसी से विवाद हुआ था। महिला ने शाहगंज पुलिस से मदद मांगी थी। उस वक्त शाहगंज थाने में तैनात दरोगा नरेन्द्र सिंह ने उसकी मदद की।

पहरण के आरोपी यूपी के विधायक का पौड़ी कोर्ट में सरेंडर, जेल भेजा

पौड़ी। करीब चार साल पूर्व यूपी के जिला पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अपरहण के आरोपी और यूपी के नगीना से विधायक मनोज पारस ने आखिरकार पौड़ी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर कर दिया है।

कोर्ट ने जमानत अरजी को खारिज करते हुए अपहरण के आरोपी विधायक मनोज पारस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 नवंबर नियत है। आरोपी विधायक मनोज पारस के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र में 2013 में बिजनौर के जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि 17 जनवरी 2013 की रात को लक्ष्मणझूला के एक होटल में ठहरे जिला पंचायत सदस्यों के कमरों में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई।

इस मामले में वारंटी विधायक मनोज पारस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में सरेंडर कर दिया। नामित अधिवक्ता जय दर्शन बिष्ट ने बताया कि विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। कोर्ट ने

जमानत अरजी खारिज करते हुए मनोज पारस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान सहित पूर्व सांसद नगीना यशवीर धोबी, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष नसरीन सैफी के पति रफी सैपी आदि सपा नेताओं को भी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था।

मनोज पारस की गिरफ्तारी को पुलिस ने दी थी दबिश

पौड़ी। जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के बहुचर्चित इस मामले में यूपी पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस ने वारंटी विधायक मनोज पारस के आवास पर दबिश भी थी। बिजनौर जिले के लोग इस मामले को भूल गए थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की दबिश कार्रवाई से तब यह मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया।

इस मामले में जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार के बेटे रोहित कुमार ने लक्ष्मणझूला में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने भी जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के इस बहुचर्चित मामले में मनोज पारस की गिरफ्तारी के लिए नगीना पुलिस के साथ दबिश भी दी थी। हालांकि तब नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिखाने पर दबिश देने गई पुलिस वापस हो गई।

भाजपा गंगा की कसम खाकर भूल जाती है जनता के वादे- अखिलेश यादव

कानपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के संकल्प को झूठ का घोषणापत्र करार दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा का यह तीसरा झूठ पत्र है जो जनता के सामने आया है। अखिलेश यहां स्टेटस क्लब में संवाददाताओं से मुखातिब थे।

अखिलेश ने कहा, भाजपा गंगा के नाम पर झूठ बोलती है। सिर्फ काली नदी ही साफ हो जाए तो बड़ा काम होगा। सपा सरकार ने गोमती और वरुणा को क्लीन करने का काम किया है। योगी सरकार जनता के साथ वैसा व्यवहार कर रही है जैसे रावण ने किया था। वह भी भेष बदलकर आया था मगर उसका अंत बड़ा बुरा हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए उससे कई गुना अधिक काम किया। सभी वादे तीन वर्ष में पूरे किए और यूपी में भाजपा अपने 8 माह के कार्यकाल में घोषणा पत्र की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। जनता को यह जानना चाहती है कि नोटबंदी से आखिर क्या मिला? उन्होंने कहा, चित्रकूट में क्या हुआ? जनता ने झूठ पकड़ लिया और वहां भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी। गुजरात में भी जनता झूठ पकड़ चुकी है। कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, थाने में हत्या हो रही है, पुलिस खुद सुपारी ले रही। जेल में बंदियों की हत्या हो रही। कानून का जंगलराज है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र, सपा की मेयर प्रत्याशी माया गुप्ता, नगर अध्यक्ष हाजी फ जल महमूद, ग्रामीण सपा

जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह यादव, विधायक अमिताभ वाजपेई, पूर्व विधायक सतीश निगम,पूर्व सांसद राकेश सचान,पूर्व नगर अध्यक्ष पं. ओम प्रकाश मिश्र, अम्बर त्रिवेदी पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया आदि मौजूद थे।

स्वच्छता अभियान पर भी निशाना

अखिलेश ने कहा, जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा के लोग मुंह में मॉस्क, हाथ में दस्ताने और झाड़ू लगाकर सड़क पर जुट जाते हैं। इसे जनता समझ रही है।

दिवाली-रमजान पर बिजली पर भरमाया

पूर्व सीएम ने कहा कि रमजान और दिवाली में बिजली के नाम पर भाजपा ने झूठ का सहारा लिया। सपा ने भरपूर बिजली दी। भाजपा कितना बिजली दे रही है? यह बता दे? अब भाजपा नफरत का विकास कर रही है।

सपा शासन में कानपुर में हुए विकास

अखिलेश ने सपा शासन में हुए विकास कार्य भी गिनाया।

पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, 2 गिरफ्तार

इलाहाबाद। निकाय चुनाव में हथियारों को खपाने की फ्राक में लगे दो तस्करों को एसटीएफ ने सोमवार को गिरफ्तार किया। ये लोग शहर में अब तक 200 पिस्टल सप्लाई कर चुके हैं। उनके पास से यूएसए व इटली मेड पांच पिस्टल, एक तमंचा, 10 मैगजीन और 50110 रुपये बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपितों ने उन लोगों के नाम का भी खुलासा किया है जिनको कुछ सालों से सैकड़ों असलहे सप्लाई करते रहे हैं।

एसटीएफ के एडिशनल एसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि निकाय चुनाव में असलहा तस्करी की सूचना पर टीम सक्रिय थी। सोमवार को इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने जीआईसी के पास से नॉर्थ मलाका निवासी सिरादउद्दीन उर्फ पप्पू और चंदौली निवासी अशोक सिंह उर्फ दुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पप्पू जार्जटाउन के असलहा तस्कर श्रवण राय के साथ मिलकर काम करते थे।

बाद में वाराणसी के आशीष सिंह से असलहे लेकर शहर में सप्लाई करने लगे। आशीष सिंह के कहने पर अशोक इलाहाबाद में पप्पू को असलहा देता था। पप्पू यूएसए मेड पिस्टल 25 हजार रुपये में बेचता था।

एसटीएफ की मानें तो कुछ सालों में पकड़े गए असलहा तस्करों ने इलाहाबाद के छात्रों को 60 पिस्टल बेची हैं। छात्रों के अलावा नैनी के गैंगस्टर पप्पू गंजिया के साथी जाने आलम को 10, गोलू को 25, आकाश पहाड़ी को 15, टार्जन को 5, करेली के आलिम को 15 पिस्टल सप्लाई कर चुका है।

एसटीएफ की पूछताछ में पता चला है कि वाराणसी का आशीष सिंह बिहार के औरंगाबाद से यूएसए मेड पिस्टल मंगाता था। औरंगाबाद में रणवीर सेना की सक्रियता के बारे में भी पता चला जो पहले नक्सलियों के साथ जुड़ी थी। अब वे असलहों की तस्करी करते हैं। इस मामले में एसटीएफ का कहना है कि वाराणसी के आशीष के पकड़ में आने के बाद राज खुलेगा।

यूपी निकाय चुनाव:

योगी ने फूंका प्रचार अभियान का बिगुल, किया जय श्री राम का उद्घोष

योगी ने भाषण का समापन करते हुए कहा, 'अपनी वाणी को देता हूं विराम, जय जय श्रीराम।' उनके यह कहते ही सभा में मौजूद लोग भी जय श्रीराम के नारे लगाने लगे।

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अयोध्या से करते हुए मंगलवार को सभा में 'जय जय श्रीराम' का उद्घोष कर प्रखर हिन्दुत्व का संदेश दे दिया।

योगी ने भाषण का समापन करते हुए कहा, 'अपनी वाणी को देता हूं विराम, जय जय श्रीराम।' उनके यह कहते ही सभा में मौजूद लोग भी जय श्रीराम के नारे लगाने लगे। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि राज्य में 653 नगर निकाय हैं, लेकिन योगी ने प्रचार अभियान की शुरुआत यहां से कर यह संदेश दे दिया कि अयोध्या के प्रति भाजपा और उनकी सरकार काफी गंभीर है। कुछ लोग इसे हिन्दुत्व से भी जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि भाजपा अयोध्या मुद्दे को सुर्खियों में बनाये रखना चाहती है, इसीलिये उसके कई नेता मौका मिलते ही राम या राम मंदिर निर्माण के सम्बन्ध में बोलने लगते हैं। योगी ने कहा कि अयोध्या के कारण ही देश दुनिया में दीपावली की शुरुआत हुई, लेकिन अयोध्या में ही यह त्यौहार समाप्ति की कगार पर था। उन्होंने तय किया था कि इस बार दीपावली में उनकी पूरी सरकार अयोध्या में रहेगी। इसका पालन करने के साथ ही 135 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। निकाय चुनाव के बाद और योजनायें शुरु की जायेंगी। उन्होंने कहा कि सात पवित्र नगरी में पहली पुरी के रुप में जानी जाने वाली अयोध्या को अन्तराष्ट्रीय पहचान दिलाया जायेगा और इसके लिये उसी के अनुरुप विकास किया जायेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकायों में 15 वर्षों तक पैसों का बंदरबाट किया गया।

ठेके नगर विकास मंत्री के लखनऊ स्थित आवास से बांटे गये। जनता को सुविधाओं से वंचित किया गया। नगर निकायों की स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो तीस फीसदी आबादी नगर निकाय क्षेत्रों में रहती है, लेकिन शेष 70 फीसदी आबादी की निर्भरता नगर इकाईयों के ईद गिर्द रहती है। केन्द्र और राज्य सरकार चाहते हैं कि नगर निकायों का समग्र विकास हो। दोनों सरकारों से आने वाला पैसों का उपयोग जनता के हित में हो। इसके लिये भाजपा के ही बोर्ड का गठन होना चाहिये।उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल, जल निकासी, बिजली, सड़क, एलईडी स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से पार्कों आदि की अच्छी व्यवस्था के लिये सही बोर्डों का गठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करवाना चाहते थे, लेकिन पूर्व राज्य सरकार ने

सहयोग ही नहीं दिया।

योगी ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि पूर्व राज्य सरकार के असहयोग की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का सटीक लाभ गरीब जनता को नहीं मिल सका। योगी ने कहा कि आवास योजना का लक्ष्य पाने के लिये शहरी निकायों में भाजपा का बोर्ड बनाना जरूरी है। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया।

उन्होंने कहा कि शहरी जनता छुट्टा गोवंश और अतिक्रमण से परेशान है। इसके लिये क्रमश: सभी 16 नगर निगमों में गौशालायें बनवायी जायेंगी तथा फेरी नीति लागू किया जायेगा। जिले के एक नगर निकाय को दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आदर्श नगर निकाय घोषित किया जायेगा। इसी तरह वार्डों का भी चयन किया जायेगा। अयोध्या में 24 घंटे बिजली,पानी देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। दुनिया में मंदिरों के शहर के रुप में मशहूर अयोध्या में सफाई और प्रसाधन की सटीक व्यवस्था होनी चाहिये। सरयू नदी की आरती के साथ ही इसकी पवित्र धारा को प्रदूषण से हर हाल में बचाया जाना चाहिये।

उन्होंने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाये रखने के लिये अयोध्या और उसके आस-पास के वासियों से भाजपा को जिताने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि नगर निकायों में संकल्प पत्र को अक्षरश: लागू किया जायेगा।

नगर निकायों की निगरानी सरकार और संगठन दोनों करेंगे। संकल्प पत्र से इतर जाने पर संगठन और सरकार दोनों का 'डंडा' पदाधिकारियों पर चलेगा। उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या नगर निगम के साथ ही करीब सभी नगर निकायों में भाजपा का झंडा लहरायेगा।

वर्ष 2017-18 के लिए 600 करोड़ का बजट मिलेगा दिल्ली विलेज विकास बोर्ड को

दिल्ली विलेज विकास बोर्ड की स्थापना को मंजूरी

गांवों में सड़क, तालाब, उद्यानों और खेल के मैदानों का निर्माण, पुस्तकालयों और व्यायामशालाओं की स्थापना, स्ट्रीट लाईट की देख-भाल करेगा विलेज बोर्ड विकास मंत्री होंगे विलेज विकास बोर्ड के पदेन अध्यक्ष, दो विधायक होंगे उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल की सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली विलेज विकास बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली विलेज विकास बोर्ड की स्थापना दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के स्थान पर की गई है।

दिल्ली विलेज विकास बोर्ड के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 600 करोड़ रपए की धनराशि निर्धारित की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि 132 करोड़ रपए थी। अब दिल्ली विलेज विकास बोर्ड राजधानी के शहरीकृत और ग्रामीण दोनों ही प्रकार के गांवों में विकास कायरे की देखभाल करेगा।

यह बोर्ड गांवों में संपर्क सड़कों के निर्माण, गांवों में लिंक रोड का निर्माण, तालाबों और जल निकायों का विकास, श्मशान के स्थलों का विकास, उद्यानों और खेल के मैदानों का निर्माण, पुस्तकालयों और व्यायामशालाओं की स्थापना, चौपाल, बारात घर और सामुदायिक केंद्रों का विकास, पीने के पानी और स्ट्रीट लाईट के कायरें की देख-भाल जैसे कार्य करेगा।दिल्ली सरकार के विकास मंत्री विलेज विकास बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और उनके अधीन सरकार द्वारा नामित दो विधायक उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे।

दिल्ली के सभी मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, एमसीडी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्य सचिव और कई अन्य अधिकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विलेज विकास बोर्ड गांवों के आधारभूत सव्रेक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुविधाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और विकास कायरे के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) का गठन किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम विकास समितियों में 21 सदस्य होंगे जिनका चयन स्थानीय विधायक करेंगे। ये सभी सदस्य स्वैच्छिक आधार पर पूरी तरह से कार्य करेंगे। विलेज डेवलपमेंट कमेटी (वीडीसी) और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए 16 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। इस समन्वय समिति के अध्यक्ष और एक सह-अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जो दिल्ली विलेज विकास बोर्ड के दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। इस समन्वय समिति के सदस्य किसी भी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

संपादकीय

दोस्ती का नया मुकाम

नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गर्मजोशीपूर्ण माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को ही बना दिया था, जब एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की बैठक में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की थी। ट्रंप ने कहा कि मोदी भारत के लोगों को एक साथ लाने में बेहद कामयाब रहे हैं। उन्होंने अद्भुत विकास हासिल करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तारीफ में भी कोई कोताही नहीं बरती। सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप की उसी सद्भावना को याद किया और कहा - 'हाल में ट्रंप जहां भी गए हैं और जब भी उन्हें भारत के बारे में बोलने का मौका मिला है, उन्होंने आशा भरी और उच्च सम्मान दर्शाने वाली बातें कही हैं। इसके आगे मोदी यह भी बोले - 'अमेरिका तथा विश्व को भारत से जो अपेक्षाएं हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि उन्हें पूरा करने का भारत भरसक प्रयास करेगा।

मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति खास सद्भाव झलका। यह मौजूदा एनडीए सरकार की सफल कूटनीति का ही नतीजा है कि दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है।

ट्रंप की इस भावना और मोदी के इरादे की झलक रविवार को भी मनीला में देखने को मिली, जब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत चतुष्कोणीय बैठक में शामिल हुआ। अमेरिका लंबे समय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऐसा समीकरण चाहता था। लेकिन पूर्व सरकारों के दौर में भारत ऐसी किसी पहल का हिस्सा बनने से हिचकता था, जिसे चीन के खिलाफ समझा जाए। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद इस नीति में व्यापक बदलाव लाई। वह खुलेआम भारत को अमेरिकी धुरी के करीब ले गई। उसी का तार्किक परिणाम मनीला में हुई बैठक है। इसमें दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन के सभी देशों के अधिकार को जताया गया। चीन ने उसका मतलब जरूर समझा होगा। इन चारों देशों ने दो-टूक कहा कि स्वतंत्र, खुले, खुशहाल और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से विश्व के दीर्घकालिक हित जुड़े हैं। इस इलाके में चीन के बढ़ते दखल के मद्देनजर यह बात बेहद अहम है। फिर चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना 'वन वेल्ट वन रोड के जरिए पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। अब दुनिया की चार बड़ी शक्तियों ने एकजुट होकर संदेश भेजा है कि चीन की मनमानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी पूर्वी एशिया यात्रा के दौरान ट्रंप ने ऐसे कई बयान दिए, जिनका भी यही अर्थ है।

मनीला में भी भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन का खास सद्भाव जाहिर हुआ। बेशक इस तमाम घटनाक्रम को मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी सफलता माना जाएगा। मनीला में प्रधानमंत्री का संवाद दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान) से हुआ। वहां उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति और यहां निहित संभावनाओं का विवरण दिया। इनमें से कई नेता वियतनाम में ट्रंप की जुबान से भारत की तारीफ सुन चुके थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत की चमकती संभावनाओं से मोहित है, तो आसियान नेताओं के लिए भारत और मोदी के महत्व को समझना अधिक आसान हो गया होगा। दुनिया में भारत की इस बढ़ती हैसियत का श्रेय एनडीए सरकार की कूटनीति को है। इसी का परिणाम प्रधानमंत्री की एक और सफल विदेश यात्रा है।

धुएं से मुक्ति की चाह

गरीबों के दिन बहुरने लगे हैं। केंद्र सरकार की गरीबों की रसोई तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की ''उज्जवला योजना' ने कई मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब गांवों की रसोई में लकड़ी, कोयला, केरोसिन के बदले एलपीजी और अन्य आधुनिक चूल्हा आ चुका है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में 67-80 फीसद परिवार आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ियों और उपलों का उपयोग करते हैं। इससे जहां महिलाओं के स्वास्थ पर बुरा असर पड़ता है, वहीं पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन बुरी तरह से बढ़ जाता है। महिलाएं खासतौर पर इससे प्रभावित होती हैं। चूंकि उदारीकरण के बाद से ही देश की तस्वीर सकारात्मक रुख लेने लगी थी और अब गांव के लोगों में भी बेहतर जीवनशैली से गुजर-बसर का विचार गाढ़ा होने लगा है। यही वजह है कि शहरों के प्रतिवर्ष आठ सिलेंडर की औसत मांग के मुकाबले गांवों में भी यह आंकड़ा औसतन प्रति वर्ष पांच तक पहुंच चुका है। यह तय इस मायने में खुशनुमा अहसास दिलाता है कि न केवल गांवों में बेहतर ढंग से खुद को स्थापित करने और शहर के मुकाबले खड़े होने का विचार दृढ़ हो रहा है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह अहम बदलाव है। अब गांवों के लोग भी स्वच्छतापूर्वक और अधिकार के साथ रहने के बारे में संजीदगी से सोचने लगे हैं, साथ ही निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, संसाधनों पर नियंत्रण, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर, बेहतर जीवनशैली अपनाने या उसका चयन करने की स्वच्छंदता, आर्थिक आजादी जैसी बुनियादी जरूरतें भी उनके आचार-विचार के केंद्र में हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो केंद्र की अगर एक योजना इतना बड़ा बदलाव ला सकती है तो बाकी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में ज्यादा परेशानी सरकार को नहीं होनी चाहिए। चाहे वह शहरों की तर्ज पर कॉलेज, अस्पताल, सिनेमाहाल और बाकी जरूरत के संस्थान हों। चाहिए तो बस मजबूत और ईमानदार इच्छाशक्ति की। सबसे अहम बात यह है कि अधिकार और सशक्तिकरण के संदर्भ में चीजें बदली हैं और कई मायनों में बेहतर भी हुई हैं। सच कहा जाए तो असल मायने में बदलाव भी यही है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

समाजवादी स्माग

दिल्ली को धुंधात्मक कोहरे ने ढक लिया है। इसे इंगलिश में स्माग कहते हैं। स्माग स्नाब के आसपास का कोई शब्द लगता है। स्नाब यानी घमंडी, नकचढ़ा टाइप, पर स्माग स्नाब नहीं है, यह एकैदम कतई जनवादी, समाजवादी है, सबके यहां घुसनेवाला। भीषण समाजवादी चरित्र का है स्माग, दिल्ली की परम इलीट बस्ती से लेकर परम दलिदर बस्ती तक स्माग है। एकदम बराबरी मचा दी है स्माग ने। इतना बेतकल्लुफ है स्माग कि घुसने की इजाजत तक मांगता। पाकिस्तान आतंकी भेजता है, भारत रोक नहीं पाता है। भारत से स्माग घुस लिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान रोक ना पाया। पाकिस्तान ने कहा भारत से कि स्माग के बवाल पर बात करो। पाकिस्तान बेवकूफ है। स्माग पर केजरीवालजी पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक से बात नहीं करते, भारत पाक बात क्या हो पाएगी स्माग पर। भारत पाक बात तो शायद कभी हो भी जाए। पर पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम की बात शायद कभी संभव ना हो। एक टीवी डिबेट स्माग पर कुछ यों चली। कांग्रेस प्रवक्ता-हमारी सरकार जब तक दिल्ली में थी, कोई स्माग का मसला पेश नहीं आता था। केजरीवालजी को सरकार चलाना नहीं आता, इसलिए स्माग आ रहा है। आप का प्रवक्ता-देखिये स्माग को लेकर कांग्रेस गलतबयानी कर रही है। भाजपा प्रवक्ता-आम आदमी पार्टी की सरकार न करप्शन दूर कर पा रही है न स्माग। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कांग्रेस के चिदम्बरम मुकदमा लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी वैचारिक धुंध में गुजर रही है। हम तो हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस प्रवक्ता-नहीं आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। आम आदमी पार्टी-कांग्रेस प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि यूपी में, हिमाचल में, कांग्रेस के बंदे भाजपा में जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के सुखराम फिर भाजपा में चले गए। एंकर-कांग्रेसी चिदम्बरम आम आदमी पार्टी सरकार के लिए लड़ रहे हैं, उसी कांग्रेस से भाजपा में लोग जा रहे हैं। सब मिले हुए हैं जी, आम आदमी पार्टी समेत। एंकर-स्माग पर आपको सरकारों से क्या उम्मीद है। आम आदमी-उम्मीद हाहाहाहा, सुबह-सुबह लाफ्टर चैलेंज चला रहे हैं क्या?

केरल की सियासत का स्याह पहलू

एस श्रीनिवासन

मई 2016 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को केरल में करोड़ों रुपये के सोलर पैनल घोटाले से जोरदार झटका लगा था। मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में यूडीएफ को विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि पी विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को जीत हासिल हुई थी। इस घोटाले की जांच कर रहे एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने पिछले हफ्ते सौंपी अपनी रिपोर्ट में ओमन चांडी को दोषी माना है, जिससे केरल की राजनीति में उबाल आ गया है। रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति जी शिवराजन के नेतृत्व वाले आयोग ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री चांडी, उनके दो मंत्रियों और कुछ विधायकों- सांसदों के साथ-साथ अनेक आईपीएस अधिकारियों द्वारा कोच्चि की एक कंपनी टीम सोलर से रिश्वत लेने का दोषी माना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी की एक निदेशक से सेक्स संबंधी लाभ भी उठाए गए।

साल 2013 में जब यह घोटाला उजागर हुआ था, तब मुख्यमंत्री चांडी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी ने अपनी पड़ताल में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक क्लर्क, एक निजी सहायक और एक सुरक्षाकर्मी के निदेशक से रिश्ते की पोल खोली थी। फोन कॉल्स के रिकॉर्ड के हवाले से एसआईटी ने मुख्यमंत्री के स्टाफ के आरोपियों के साथ लगातार बातचीत और उसमें सेक्स संबंधी बातों से परदा उठाया था। ये कर्मचारी न सिर्फ तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जांच में 'टीम सोलर' एक धोखेबाज कंपनी के रूप में सामने आई, जो लोगों से यह कहकर धन उगाह रही थी कि आला सरकारी अधिकारियों के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं और वह उन्हें आसानी से कनेक्शन दिला देगी। आरोप यह भी था कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों के दफ्तर के साथ संपर्क का फायदा ठेके हासिल करने के लिए भी उठाया गया। एक स्थानीय कारोबारी बीजू राधाकृष्णन और उसकी लिव-इन पार्टनर, जिन्होंने टीम सोलर कंपनी शुरू की थी, भाले-भाले लोगों को सौर ऊर्जा कनेक्शन दिलाने का वादा करके ठग रहे थे और इन्हीं ग्राहकों में से एक की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार हुए थे।

यह एक पोंजी योजना थी, जो गलत दिशा में मुड़ गई। दरअसल, टीम सोलर ग्राहकों और निवेशकों से इस उम्मीद के साथ अग्रिम राशि वसूलती थी कि नए ग्राहकों से धन उगाही के बाद उन्हें पुनर्भुगतान होता रहेगा। अपनी सार्वजनिक छवि चमकाने के लिए कंपनी महत्वपूर्ण लोगों को अवॉर्ड भी देती थी। कंपनी इन आयोजनों में मीडिया के साथ-साथ बड़े अधिकारियों, सांसदों-विधायकों को न्योता देती थी। एकाधिक बार तो उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान भी दिया था। इन आयोजनों के जरिए कंपनी और इसके निदेशक मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों-विधायकों से अपनी सच्ची-झूठी घनिष्ठता की कहानी प्रचारित करती थी।

न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले में संलिप्त सरकारी अफसरों के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट' के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि इस आरोप में 'दम' है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री टी राधाकृष्णन ने जांच को प्रभावित करने की चेष्टा की और इसी कारण उनके पुलिस प्रमुख और एसआईटी मुखिया ने जांच को 'नुकसान पहुंचाने' का प्रयास किया। मुख्यमंत्री पी विजयन ने आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के लिए न सिर्फ विशेष सत्र बुलाया, बल्कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुरूपजांच के लिए एक और एसआईटी का गठन भी किया है। विजयन ने एक ऐसे प्राधिकरण के गठन की भी घोषणा की, जो इस बात की निगरानी कर सके कि कैसे 'पुलिस बल को अनुशासित रखा जाए'। जिस तरह से पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री चांडी को आपराधिक जिम्मेदारी से 'मुक्त करने' की कोशिश की, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने यह कदम उठाया है।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों द्वारा 33 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस का अनुमान था कि दोनों आरोपियों ने लोगों से करीब छह करोड़ रुपये उगाहे थे। यह भी आरोप था कि कुछ नामचीन शख्सीयतों ने भी अपना काला धन इसमें निवेश कर रखा था। जाहिर है, जब एक पीड़ित ने इस योजना के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर शिकायत की, तो कई सारे अन्य लोग भी अपनी शिकायतों के साथ उससे जुड़ गए, परिणामस्वरूप यह योजना ही धराशायी हो गई। शुरुआत में इस मामले में सेक्स संबंधी पहलू उजागर नहीं हुआ था। यह मामला तब सामने आया, जब निदेशक को एर्नाकुलम कोर्ट में पेश किया गया। उसने अदालत को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उसका 'यौन शोषण और बलात्कार' किया। तब उससे लिखित में विस्तार से अपनी बात कहने को कहा गया। उसने एक पत्र लिखा है, जिसे आयोग की रिपोर्ट में प्रमुखता से दर्ज किया गया है। वह पत्र विस्फोटक था। निदेशक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों- नेताओं द्वारा अपने यौन-शोषण और चांडी को 2.16 करोड़ रुपये की रिश्वत अपने हाथों से देने की बात विस्तार से लिखी है।

आयोग ने इन तमाम आरोपों की गहराई से जांच की अनुशंसा की है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अद्वितीय एकजुटता दिखाते हुए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चांडी ने खुद एलान किया है कि अगर आरोप साबित हुए, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या इन आरोपों को गंभीरता से लिया जा सकता है? इस निदेशक के खिलाफ विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के 40 मुकदमे चल रहे थे। फिर वह लगातार अपने बयान भी बदलती रही है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर उसके जो कटु अनुभव हुए हैं, खासकर औरत होने के नाते, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर उसके बयानों को गौर से देखा जाए, तो वे केरल की राजनीतिक संस्कृति की सड़ांध को उजागर करते हैं। हालांकि, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद चांडी की साख अब तक बहुत खराब नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक, लोग यह मानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को भले बढ़ावा दिया हो, मगर वह दुराचार में शामिल नहीं हो सकते। बहरहाल, पूरी सच्चाई मुकम्मल जांच से ही सामने आ पाएगी। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम यूडीएफ के लिए बड़ा झटका तो है ही, खासकर उस वक्त पर, जब खुद एलडीएफ के मंत्रियों के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्य के आरोप लग रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> भ्रष्टाचार का एक मामला आरोपों के जिस निचले स्तर पर पहुंच गया, उससे राज्य की राजनीति की सड़ांध को समझा जा सकता है।

प्रसंगवश

बेघरों के प्रति निष्ठुर सरकारें

अनूप भटनागर

क्या सहजता से इस तथ्य पर यकीन किया जा सकता है कि देश के 90 फीसदी शहरी गरीबों के पास कड़ाके की सर्दी और भीषण गर्मी के मौसम में सिर छिपाने की जगह नहीं है। वह भी ऐसी स्थिति में जब केन्द्र सरकार ने इन बेघरों के लिये स्थाई आश्रयों के निर्माण हेतु 2185 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई, लेकिन राज्य सरकारें इसमें से आधी रकम का भी उपयोग नहीं कर सकीं। इसी से देश में शहरी और ग्रामीण बेघरों के प्रति राज्य सरकारों की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है।

यही वजह है कि न्यायालय को यहां तक कहना पड़ा कि इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि सीधे बेघर लोगों के कल्याण के लिये ही जारी की जानी चाहिए। न्यायालय ने तो यह भी संकेत दिया कि यदि यही स्थिति रही तो वह बेघर लोगों से संबंधित स्थिति की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर समितियां गठित करने पर विचार कर सकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 18 लाख बेघर थे। इनमें से करीब दस लाख शहरी क्षेत्रों में और शेष ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। यही नहीं, शहरी बेघरों में से करीब 65 प्रतिशत बेघर उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में रहते हैं।

इसी जनगणना के आधार पर केन्द्र सरकार ने एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले 790 शहरों और नगरों के लिये 2013 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीब बेघरों के लिये हर मौसम में काम आने वाले स्थाई आश्रयों के निर्माण की योजना शुरू की थी। इसके लिये केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को धन भी उपलब्ध कराया मगर केन्द्रीय सहायता मिलने के बावजूद शहरी बेघर अभी भी सड़कों, फ्लाईओवर के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इस योजना के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता को देखते हुए देश की शीर्ष अदालत को केन्द्र से यहां तक कहना पड़ा कि आप अच्छी योजना तैयार करते हैं लेकिन यदि उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो सकता है तो फिर इन्हें बनाया ही क्यों जाता है। न्यायाधीशों ने कहा कि केन्द्र से हजारों करोड़ रुपये मिलने के बाद भी कल्याणकारी योजनाओं पर अमल नहीं होना काफी निराशाजनक है। अगर यही स्थिति है तो फिर इन योजनाओं को खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाता क्योंकि इन पर कारगर तरीके से अमल नहीं होने की वजह से करदाताओं के धन की बर्बादी हो रही है।

न्यायाधीशों की इस तरह की तल्ख टिप्पणियों से शहरी गरीब बेघरों को आश्रय मुहैया कराने के मामले में राज्य सरकारों की कार्यशैली का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। न्यायालय ने अब राज्यों से इस धन के उपयोग के बारे में सिलसिलेवार विवरण प्राप्त करने का निश्चय किया तो इनमें से कई के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। शहरी बेघरों के लिये केन्द्र की योजना के परिप्रेक्ष्य में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कैलाश गंभीर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिये आश्रय निर्माण करने की योजना पर अमल की वस्तुस्थिति का पता लगाना था।

समिति ने अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट अगस्त महीने में न्यायालय को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि केन्द्र से धन मिलने के बावजूद राज्य सरकारें बेघरों के लिये स्थाई आश्रयों का निर्माण करने में पूरी तरह विफल रही हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जहां दिल्ली और मिजोरम के प्रदर्शन की सराहना की वहीं इस योजना के अमल के मामले में चिंताजनक प्रदर्शन के लिये 11 राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों का विशेष उल्लेख किया गया था।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के लिये उन्हें आड़े हाथ लिया। न्यायाधीशों का कहना था कि बेघरों के प्रति राज्य सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए लेकिन शायद वे हैं नहीं। इसी वजह से धन उपलब्ध होने के बावजूद राज्यों में शहरी बेघरों के लिये पर्याप्त संख्या में स्थाई और अस्थाई आश्रयों का निर्माण नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा कि समझ में नहीं आता कि कैसे सरकारें इन बेघरों के प्रति चिंतित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये बेघर उनके लिये सिर्फ एक संख्या बनकर रह गये हैं। हालांकि इस मामले में न्यायालय अब दो सप्ताह बाद फिर विचार करेगा लेकिन फिलहाल यह उम्मीद की जानी चाहिए कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए राज्य सरकारें बेघरों के लिये आश्रयों के निर्माण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम तेज करेंगी ताकि मौसम की मार से किसी निर्दोष की जान न जाए।

पं. नेहरू

एक विचारक राजनेता

जाहिद खान

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विचारक राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय योगदान है। परतंत्र भारत में पंडित नेहरू का महत्व जहां देश को स्वतंत्र कराने के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों के चलते है, तो वहीं स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा आधुनिक जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार की वजह से। जातीय और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद उन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। नेहरू देश को वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास के आधुनिक दौर में ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अगाध आस्था थी और वे चाहते थे यही आस्था देशवासियों के दिल में भी हो। लिहाजा, इसके लिए उन्होंने अनथक प्रयास किए। नेहरू समाजवादी विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। समाजवादी विचारधारा का ही का प्रभाव था कि उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। लोकतंत्र, समाजवाद, एकता और धर्मनिरपेक्षता उनकी घरेलू नीति के चार ठोस स्तंभ थे। अपने आखिरी वक्त तक वे इन्हीं नीतियों पर कायम रहे। जातीय और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। वे साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे। नेहरू मौजूदा दौर के राजनेताओं की तरह उथले विचारों वाले नेता नहीं थे, न ही वे बड़बोले थे। वे जो भी बोलते, सोच समझकर बोलते। नेहरू द्वारा समय-समय पर दिए गए भाषणों का यदि अध्ययन करें, तो मालूम चलता है कि उनकी सोच कितनी आगे थी।

किसी भी मसले पर उनके विचार निकालकर देख लीजिए, वे जितने उस वक्त प्रासंगिक थे, आज उससे भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। पं. नेहरू साम्प्रदायिकता को पिछड़ेपन की निशानी मानते थे। 19 जुलाई 1961 को श्रीनगर में दिए अपने भाषण में कश्मीरवासियों को समझाइश देते हुए कहा था, ''राजनीति में धर्म या मजहब को लाना और देश को तोड़ना वैसा ही है, जैसा कि तीन सौ या चार सौ वर्ष पहले यूरोप में हुआ था। भारत में हमें इस चीज से अपने आपको दूर रखना होगा।' अपने इसी भाषण में वे उन लोगों को आगाह करते हैं, जो राष्ट्रवाद की सतही परिभाषा करते हैं। ''साम्प्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद या सिख राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। ज्यों ही आप हिंदू, सिख, मुसलमान की बात करते हैं, त्यों ही आप हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते।' जाहिर है उनकी नजर में राष्ट्रवाद की परिभाषा संकीर्ण नहीं। भारत का जिस तरह का चरित्र है, उसमें सिर्फ हिन्दू राष्ट्रवाद की बात करना, अंततः देश का नुकसान करना है। हिन्दुस्तान का तसव्वुर किसी एक धर्म या मजहब को लेकर नहीं किया जा सकता। ये देश कई धर्मो और पंथों से मिलकर बना है। इसी भाषण में वे कहते हैं, ''अलगाव हमेशा भारत की कमजोरी रही है। पृथकतावादी प्रवृत्तियां चाहे वे हिन्दुओं की रही हों या मुसलमानों की, सिखों की या और किसी की, हमेशा खतरनाक और गलत रही हैं। ये छोटे और तंग दिमागों की उपज होती हैं। आज कोई भी आदमी जो वक्त की नब्ज पहचानता है, साम्प्रदायिक ढंग से नहीं चल सकता।' आजादी के तुरंत बाद 13 दिसम्बर 1947 को इलाहाबाद विविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, ''अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में हमारी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य स्वतंत्र, साक्त और लोकतंत्री भारत है। हम चाहते हैं कि भारत सशक्त, स्वाधीन और लोकतंत्री हो, जहां हर नागरिक को समान स्थान और तरक्की व सेवा के समान अवसर मिलें, जहां आजकल की जैसी धन-संपत्ति और हैसियत की असमानताएं मिट जाएं, जहां हमारा उत्साह और भावनाएं रचनात्मक और सहकारी अध्यवसाय की दिा में काम करें। धर्म जहां स्वतंत्र रहेगा, लेकिन उसे राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक और राजनीतिक पक्ष में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई के ये सब झगड़े राजनीतिक जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।' कुल मिलाकर आज हम जो आधुनिक, सशक्त, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत देख रहे हैं, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता और प्रगतिशील दृष्टिकोण का ही नतीजा है। इसे अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

निकाय चुनाव: 3 शहरों से योगी ने शुरु किया प्रचार

लखनऊ.निकाय चुनावों के लिए सीएम योगी ने मंगलवार से प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अयोध्या नगर निगम को तरजीह देते हुए प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की है। इस दौरान योगी ने फैजाबाद में अपील की है कि बीजेपी को बहुमत से जिताएं ताकि किसी भी योजना का लाभ सरकार शहर को दे सके।

फैजाबाद-अयोध्या

2012 में हुए नगर निकाय चुनावों में फ़ैजाबाद-अयोध्या नगर निगम में नहीं था। तब यहां 2 नगर पालिका थी, जिसमे फ़ैजाबाद और अयोध्या शामिल थी। इन दोनों में ही बीजेपी का अध्यक्ष था।

वर्तमान में 60 पार्षद की सीट है। जबकि 2012 में इससे कम सीटें थी लेकिन वर्चस्व बीजेपी का ही था।

वहीं, विधानसभा की 5 सीटें यहां पर है, जिनमे से 2017 में पांचों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी फ़ैजाबाद-अयोध्या में मजबूत दिखाई दे रही है।

गोंडा

गोंडा में 4 नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत हैं। इनमे 2012 में कहीं भी बीजेपी नहीं थी।

2012 में गोंडा शहर से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय व्यक्ति ने जीता था। यही हाल नगर पंचायत में भी रहा जहां सपा और बसपा का कब्जा था।

अबकी बार तस्वीर बदल गई है, 2017 विधानसभा चुनाव में गोंडा जिले की 7 सीटों पर बीजेपी ने ही कब्ज़ा जमाया हुआ है।

2012 विधानसभा चुनावों में जहां यहां सपा का कब्ज़ा था तो वहीं, अबकी बार बीजेपी ने सपा का सूपड़ा साफ़ कर दिया था लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात है।

बहराइच

वहीं, बहराइच जिले में भी योगी ने निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुमत से लाने की अपील की है। दरअसल, पिछले 10 सालों से यहां 2 नगर पालिका परिषद में से एक में सपा तो दुसरे में बसपा का ही कब्ज़ा रहा है।

बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा सीट में से 6 पर कब्ज़ा किया है। लेकिन इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि पहले दिन रैलियों में योगी ने बहराइच को प्राथमिकता दी है।

इस हाल में थी लेडी की लाश-रूम में खून ही खून

मेरठ. यहां के थाना टीपीनगर की गोकुल विहार कालोनी में एक महिला की फावड़े से वारकर हत्या कर दी गई। महिला का पति मौके से फरार है, महिला के परिजनों ने पति पर ही हत्या कर फरार होने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

6 साल पहले हुई थी शादी

गोकुल विहार कालोनी में रहने वाले ऋषपिाल ने 6 साल पहले सोनिया से शादी की थी। शादी के बाद दोनों को एक लड़का है। मंगलवार सुबह सोनिया का शव उसके कमरे में पड़ा मिला, फर्श पर चारों ओर खून बिखरा पड़ा था।

पास ही खून से सना एक फावड़ा रखा था, साथ ही कुछ आपत्तजिनक सामान (कंडोम) भी मिला है। जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

रामलीला में आगे बैठने को लेकर विवाद, 2 दोस्तों को सरेआम मार दी गोली

कन्नौज.यूपी के कन्नौज में रविवार को रामलीला देखने पहुंचे कुछ बदमाशों का आगे बैठने को लेकर एक युवक से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने युवक और उसके एक साथी को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, घायल की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे में धुत्त से आरोपी...

दर कोतवाली क्षेत्र के अटारा में कुछ दिनों से रामलीला का आयोजन हो रहा था। रविवार रात मृतक धर्मसिंह(18) अपने साथी सर्वेश के साथ गांव में चल रही रामलीला देखने गया था। इस दौरान सिमरापुर निवासी अजय अपने दो साथियों के साथ रामलीला देखने पहुंचा।

नशे में धुत्त अजय का आगे बैठने को लेकर धर्मसिंह से झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी अजय ने धर्मसिंह और उसके साथी पर तमंचे से गोली चला दी। गोली लगने से धर्मसिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी सर्वेश घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एएसपी केशव चंद्र गोस्वामी और कोतवाल एके सिंह ने शव को कब्जे में लेकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत में सर्वेश को कानपुर रेफर कर दिया गया।

क्या कहती है पुलिस

कन्नौज एसपी हरीश चन्दर का कहना है, ''इस मामले मे 3 लोगों के खिलाफ हत्या और दबंगई का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, घायल युवक खतरे से बाहर है। बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।''

अन्ना प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने दिए थे 100 करोड़, हालात में नहीं हुआ सुधार

झांसी.बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों के लिए 7700 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया था। इस पैकेज में एक अरब रुपए सिर्फ अन्ना प्रथा को खत्म करने के लिए थे। पूरे 1 अरब रुपए खर्च भी हो गए लेकिन अन्ना प्रथा कोई सुधार नहीं हुआ। सदियों से चली आ रही अन्ना प्रथा अब किसी विपदा से कम नहीं हैं। केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने दिया था बजट...

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भानू सहाय ने बताया, जब 2009-10 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय 7700 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड विशेष पैकेज दिया गया था जिसमें 100 करोड़ रुपए अन्ना प्रथा के लए दिए गए थे। लेकिन अब आलम यह है कि मौजूदा स्थिति में अन्ना प्रथा और इजाफा हो गया है। सरकारी आकड़े बतातें है कि झांसी मंडल में 5 लाख अन्ना पशु है जिनमें से 1.65 लाख तो गाए हैं। चित्रकूटधाम मंडल का हाल तो इससे कहीं ज्यादा चौकाने वाला है पूरे मंडल में कुल 19.49 लाख मवेशी हैं। इनमें 12.90 लाख गायें दर्ज हैं।

बुंदेलखंड में लगातार पड़ने वाले सूखे और अनाज की कमी की वजह से हजारों लोगों ने यहां से पलायन तो किया ही है साथ ही चारे की कमी की वजह से जानवरों को भी जान गंवानी पड़ रही है।

डिमरौनी के रहने वाले हरगोविंद बताते हैं, ''हमारे गांव से लगा हुआ वन विभाग का जंगल है। आसपास के जितने भी गांव वाले हैं वे सभी इसी जंगल में गायों को छोड़ जाते हैं। ये गायें हर साल हमारी 30-35% फसल बर्बाद कर देती हैं। हाईवे पर प्रतिदिन 3-4 गायों के एक्सिडेंट हो जाते हैं। जिनमें से ज्यादातर गायों की मौत हो जाती है।''

बाल-बाल बचे साक्षी महाराज, टैंकर ने मारी बीजेपी सांसद की कार को टक्कर

एटा। दिल्ली से एटा लौटे रहे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की कार को दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर की इस घटना में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बाल-बाल बच गए। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। घटना हाथी गेट के पास नेशनल हाईवे-91 की है, जहां शिकोहाबाद की तरफ से आ रहे दूध के टैंकर ने साक्षी महाराज को टक्कर मारी है। इतना ही नहीं साक्षी महाराज की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद इस टैंकर ने दो और बाइक को टक्कर मारी।

राजधानी में स्मॉग का असर, कूड़ा जलाने पर होगा जुर्माना

लखनऊ. पिछले दिनों में स्मॉग के कारण प्रदूषण जांच रिपोर्ट में राजधानी टॉप पर रही है। अभी भी यहां एयर पोल्यूशन दूसरे शहरों की अपेक्षा काफी अधिक है। बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नगर आयुक्त उदय राज सिंह ने निर्देश दिए हैं- ''शहर के किसी भी क्षेत्र, गली, महल्ले में कूड़ा न जलाया जाए।'' सफाईकर्मियों अथवा पब्लिक द्वारा सफाई के उपरांत कूड़े के ढेर बना दिए जाते हैं जिसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है।'' लगाया जाएगा जुर्माना

उन्होंने कहा- नियमित रूप से कूड़े को न जलाए जाने के संबंध में

जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिया गया है। कूड़ा जलाते हुए पाया जाने पर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कूड़ा जलाते हुए पाया जाने पर उसके विरुद्ध पर्यावरणीय नियम के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करायी जाएगी।

सड़क के किनारे एकत्रित मलवा एवं निर्माण सामग्री के हटाए जाने एवं जुर्माना वसूल किए जाने के संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। यदि किसी भी क्षेत्र में मलबा अथवा निर्माण सामग्री सड़क के किनारे अवैध रूप से पायी जाती है तो इसके लिए नगर अभियंता उत्तरदायी होंगे।

इन विभागों को भेजा गया पत्र

नगर आयुक्त की ओर से कई विभागों को भेज कर सहयोग मांगा गया है। इसमें एलडीए, आवास-विकास परिषद, व सिंचाई विभाग हैं। निर्माण कार्य के दौरान वातावरण प्रदूषित न होने के संबंध में एलडीए एवं आवास विकास परिषद से कहा गया है- ''विभाग अपने स्तर से समस्त ठेकेदार व डेवेलपर्स को निर्देश जारी करें कि निर्माण सामग्री को सड़क पर न रखकर अपने कैम्पस के भीतर ही रखें।'' मिट्टी की लेवलिंग एवं ड्रेसिंग का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए।

बिहार

नीतीश कुमार बोले- अब लोकसभा में पेश हो महिला आरक्षण बिल

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। जदयू अपनी सीमित ताकत में भी इसका समर्थन करेगा। सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय भी राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक का हमारी पार्टी ने समर्थन किया था। इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर वंचित तबके के साथ भेदभाव होगा। बिहार में हमारी सरकार ने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया था। इससे सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

' गोरक्षकों ' पर पीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'गोरक्षकों' के मुद्दे पर मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है। वे सहमत हैं कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डीजीपी व गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370, समान आचार संहिता और अयोध्या विवाद पर मैं अपने पुराने रुख पर कायम हूं।

कॉन्ट्रेक्ट-आउटसोर्स, दोनों में लागू होगा आरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग कृषि संकट से जुड़ा मुद्दा है। न सिर्फ पाटीदार बल्कि जाट, मराठा और अन्य समुदाय जो कृषि से जुड़े हुए हैं, हम उनके आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं। इसका पॉलिटिकल लेना देना नहीं है। इसके लिए राजकोष से उस कंपनी को धन मुहैया कराया जाता है। स्वाभाविक है कि सरकारी धन के उपयोग पर रिजर्वेशन एक्ट को मानना पड़ेगा।

पति ने दहेज के लिए प्रेग्नेंट पत्नी को बोला तीन तलाक

गया। बिहार के गया जिले में एक पति ने ससुराल से पत्नी को घर लाया। घर लाने के बाद गेट पर ही तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद प्रेग्नेंट पत्नी की पिटाई करने लगा। फिर सादे कागज पर साइन कराकर घर से निकाल दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए पति प्रताड़ित भी करता था। बच्चों को मिलने से रोका...

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गया के मानपुर अबगिल्ला जगदीशपुर निवासी नाजिया प्रवीण की शादी 2007 में परवेज आलम के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही नाजिया को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। शादी के प्रीतिभोज के दिन ही परवेज आलम ने बाइक की मांग की थी।

रेलवे ने वैकेंसी निकाली ही नहीं, मंत्री कोटा के नाम पर 12 से 3 लाख वसूले

दिघवारा (छपरा)। दिघवारा थाना क्षेत्र के शीतलपुर में दलालों ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 12 से अधिक अभ्यर्थियों से करीब 40 से 50 लाख रुपए वसूली की है। अभी और अभ्यर्थियों की शिकायत थाने पहुंच रही है। इस मामले में पीड़ितों ने छपरा न्यायालय में परिवाद दायर कर गुहार लगाई है।

इस बाबत नयागांव थाना क्षेत्र के निवासी उमेश प्रसाद के पुत्र आर्यन राज ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र पेश कर न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। जिसमें कोर्ट ने दिघवारा थाना को प्राथमिकी दर्ज करा कर कार्रवाई का आदेश दिया है। दिए गए परिवाद पत्र में दिघवारा थाना क्षेत्र के सितलपुर गांव के चार लोगों को आरोपित किया गया है।

इसी गिरोह पर आरोप लगाया गया है कि ये लोग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर हर अभ्यर्थियों से तीन से चार लाख रुपए की वसूली की है। जिसमें नौ लोगों से मंत्री व अधिकारी के कोटा से रेलवे में ग्रुप डी व सी पद पर बहाल कराने के लिए तीन से चार-चार लाख रुपए ठगे हैं। इस बाबत न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दिघवारा थाना को प्राथमिकी के लिए परिवाद भेज दिया है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में संगठित गिरोह सक्रिय है। उसने कहा है कि इस मामले में आरोपियों ने यह कह कर पैसे की वसूली की है कि आप लोगों को कोलकत्ता में पहले ट्रेनिंग दिलाई जाएगी उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा।

कोलकाता में तीन माह की दी गई ट्रेनिंग

परिवाद पत्र दाखिल करने वाले ने बताया गिरोह द्वारा बाजाब्ता रेलवे में नौकरी के नाम पर उम्मीदवारों को कोलकाता के कचड़ा पारा नामक जगह पर 3 माह तक प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। प्रशिक्षण के बाद गायब हो गया। कचड़ा पाड़ा में ट्रेनिंग के बाद जब उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग दिलवाने की कहीं गई तो धीरे धीरे सभी आरोपित गायब हो गए।

ट्रेनिंग के बाद होनी थी ज्वाइंनिंग, दौड़ा रहे थे

उसने कोलकाता में ट्रेनिंग भी दिलाई। लेकिन ज्वाइंनिंग की बारी आई तो दौड़ाने लगा। आवेदक ने न्यायालय में विभिन्न तरह के साक्ष्य जो आरोपितों द्वारा उपलब्ध कराए गए उसकी छाया प्रति भी न्यायालय में समर्पित किया है। आवेदक आर्यन राज के अलावा दिलीप कुमार, बलवंत कुमार पंकज, सुशील कुमार समेत अन्य है।

पैसा वापस मांगने पर आरोपित दे रहे हैं धमकी

पीड़ितों को जब अपनी ठगी का अहसास हुआ तब वह आरोपितों से पैसा वापस मांगा ।जिस पर आरोपित ने उसे धमकाना शुरू कर दिया ।

दिघवारा थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि इस मामले में न्यायालय से परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया जायेगा ।गिरोह का पता लगा कर गिरफ्तार किया जाएगा।

इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभिकर्ताओं के द्वारा तरैया-इसुआपुर-पानापुर के लोगों से रुपए दुगना करने के नाम पर 50 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। भागवतपुर के अभिकर्ता लालबाबू राय, डेवढ़ी के तारकेश्वर प्रसाद, अटौली के लखींद्र प्रसाद, धेनुकी के राजू सिंह आदि सहित 25 अभिकर्ताओं ने सारण डीएम, मढ़ौरा एसडीओ एवं गोपनीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक शिकायत प्रतिवेदन भेज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

छपरा में बनेगा डबल डेकर, सड़क बनाने में खर्च होंगे 20 हजार करोड़

छपरा। जून 2018 से उत्तर भारत के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फ्लाई ओवर निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यह बात सूबे के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने सोमवार को कही। सारण अंचल में सड़क व पुल निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद यादव सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सारण अंचल में एनएचआई, एसएच, पुल व अन्य जितनी भी सड़कें हैं, सबकी समीक्षा की गई। दिसंबर 2018 से पहले सभी सड़कों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि गांधी सेतु के रिस्ट्रक्चर का कार्य तेजी से चल रहा है। सुपर स्ट्रक्चर को हटाकर नया कार्य हो रहा है। दिसंबर 2018 तक गांधी सेतु का पश्चिमी लेन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। सितंबर 2019 तक पूर्वी लेन को भी ठीक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गांधी सेतु से पश्चिम दिशा में पुल बनेगा।

पहलेजा से दीघा तक एक और टू लेन सड़क पुल होगा

पहलेजा घाट से दीघा तक एक और टू लेन सड़क निर्माण कराने की बात मंत्री ने कही। इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। दीघा सड़क के पास ही यह टू लेन सड़क पुल बनेगा। उन्होंने कहा कि इस टू लेन के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों के अलावा मुजफ्फरपुर व वैशाली के लोगों के लिए भी आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

छपरा से होकर गुजरेगी राम-जानकी सड़क

अयोध्या से मिथिला को जोड़ने वाली राम-जानकी पथ छपरा से भी गुजरेगी। मंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से जगत जननी सीता की जन्मभूमि मिथिला को जोड़ने वाली रामजानकी पथ सारण अंचल में अफराद मोड़ से मशरक, राजापट्टी, सत्तरघाट पुल, केसरिया होते हुए नेपाल तक जाएगी।

पटना रिंग रोड में शामिल होगा छपरा भी

राज्य सरकार ने सड़क की योजना बनाई है। जिसका नाम पटना रिंग रोड है। पटना रिंग रोड में वैशाली के साथ छपरा भी शामिल होगा।

बस के नीचे बाइक आने से युवक की हुई मौत

भागलपुर। भागलपुर-अमरपुर रोड पर हबीबपुर थाने के पास सोमवार सुबह 9.30 बजे सिंहवाहिनी बस से कुचल कर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपनी बहन की तैयारियों में जुटा था। घटना के विरोध में लोगों ने साढ़े तीन घंटे तक सड़क जमा रखा और हबीबपुर थाने के सामने प्रदर्शन किया। गेट को तोड़ कर भीड़ थाना कैंपस में घुसने का प्रयास कर रही थी।

बड़ी बहन को बाइक से ले आने जा रहा था मृतक

मौके पर पहुंची हबीबपुर पुलिस को भी शुरुआत में खदेड़ दिया और घटनास्थल से लाश को उठने नहीं दिया। परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। मृतक 22 साल का मो. रिजवान छोटी साहेबगंज का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक, रिजवान अपनी बड़ी बहन बीबी शामका के घर हबीबपुर भांजा अरशद को बाइक से लाने जा रहा था। हबीबपुर थाने से पहले किसान कोल्ड स्टोरेज के पास सामने से आ रही यात्री बस ने उसे रौंद दिया। मौके पर ही रिजवान की मौत हो गई। उसकी बाइक बस के नीचे घुस गई। दुर्घटना के बाद बस और उस पर सवार यात्रियों को छोड़ कर ड्राइवर फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सभी यात्रियों को नीचे उतार कर बस में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की। बस में आग लगाने के सवाल पर आपस में ही ग्रामीण भिड़ गए और मारपीट करने लगे।

छह इंच टूटे ट्रैक पर दौड़ी मालदा इंटरसिटी, ड्राइवर ने रोकी ट्रेन, बचे 2000 यात्री

भागलपुर। मालदा रेलखंड पर सबौर और लैलख स्टेशन के बीच सोमवार शाम बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पर 292 किलोमीटर के छठे और सातवें खंभे के बीच छह इंच रेल लाइन टूट गई। शाम 5.45 बजे दानापुर-मालदा इंटरसिटी टूटी रेल लाइन पर दौड़ी और इंजन और पहला कोच गुजर गया। ड्राइवर और गार्ड ने सावधानी बरती और तत्काल ट्रेन रोक दी। इससे ट्रेन में सवार करीब 2000 लोग बाल-बाल बच गए।

बड़ा हादसा टल गया। करीब सवा दो घंटे की मशक्कत के बाद टूटी पटरी को ज्वॉइंट लगाकर दुरुस्त किया गया। इसके बाद ट्रेन रात 8 बजे रवाना हुई। शाम 5.45 बजे दानापुर-मालदा इंटरसिटी लैलख की ओर जा रही थी। सबौर से निकलकर ट्रेन लैलख पहुंचने ही वाली थी कि रेलखंड के 292 किलोमीटर के छठे और सातवें पोल के बीच अचानक तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने आवाज सुनकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन का इंजन और इंजन के पीछे लगा एसएलआर कोच आगे निकल चुका था। ट्रेन रूकी। ड्राइवर और गार्ड नीचे उतरे तो पता चला, रेल लाइन छह इंच तक टूट गई है।

मचा हड़कम्प, दहशत में आ गए रेलयात्री

बीच रास्त में अचानक रूकी ट्रेन से यात्री उतरे तो उन्हें भी पता चल गया कि ट्रैक टूट चुका है। टूटे ट्रैक की जानकारी मिलते ही 14 कोच वाली ट्रेन में हंगामा मच गया। यात्री डर गए। सभी ट्रेन से नीचे उतर आए। ड्राइवर और गार्ड ने सभी को समझाया। उन्हें शांत करवाया। इसके बाद रेल कंट्रोल को सूचना दी।

स्टेशन प्रबंधक ओंकार प्रसाद ने बताय कि रेल लाइन अचानक क्रेक हो गया। इससे सवा घंटे ट्रेन लैलख और सबौर रेल लाइन के बीच खड़ी रही। भागलपुर से इंजीनियरों की टीम भेजी गई और पटरी को ठीक कराया गया। इसके बाद ट्रेन का परिचालन सामान्य हुआ।

रेलवे की टेक्निकल टीम पहुंची तुरंत पहुंची घटना स्थल पर

सूचना पाकर भागलपुर से पीडब्ल्यूआई केके राय के साथ टैक्निकल टीम मौके पर पहुंची। टूटे ट्रैक को देखा और काम शुरू किया। लेकिन शाम गहराने से अंधेरा पसरा तो काम में भी परेशानी हुई।

श्रम आयुक्त कार्यायलय सहित सभी स्कूलों में विश्व बाल दिवस का भव्य आयोजन

सूरत। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को नायब श्रम आयुक्त कार्यालय, सूरत में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। नायब श्रम आयुक्त जी.एल. पटेल तथा सहायक श्रम आयुक्त एस.एस.गांधी की अध्यक्षता में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट संचालित प्रोजेक्ट में सूरत जिले के अलग-अलग 20 विद्यालयों में प्रथम एजूकेशन प्रथम चाइल्ड हेल्प लाइन(1098), जीगर बाल कल्याण ट्रस्ट, सुरचना एजुकेशन ट्रस्ट, समता ट्रस्ट तथा अन्य स्वैचिछक संस्थाओं के सहयोग से जन जागृति रैली निकाली गई। साथ ही बच्चों के खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

जिले के सभी 16 विधानसभा सीटों के लिए 21 नवंबर तक भरे जाएंगे उमीदवारी पत्रक

सूरत। गुजरात विधानसभा आम चुनाव-2017 के लिए सूरत जिले के 16 विधानसभा सीटों के लिए उमीदवारी पत्रक भरने का काम 14 नवंबर से शुरू हो गया जो 21 नवंबर तक चलेगा। सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर उमीदवारी पत्रक भरने का काम प्रतिदिन प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। उमीदवारी पत्र की जांच का काम 22 नवंबर को किया जाएगा। 24 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक उमीदवारी पत्रक वापस लिया जा सकेगा। 9 दिसंबर की सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक मददान किया जाएगा।

अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के उमीदवारों को अपने-अपने क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों में उमीदवारी पत्रक जमा करना होगा। जो इस प्रकार है-

155-ओलपाड़ विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक ओलपाड़ प्रांत अधिकारी कार्यालय, तालुका सेवा सदन, हाथीसा रोड, ओलपाड तथा मामलतादार कार्यालय, तालुका सेवा सदन, ओलपाड में निर्धारित तारीख व समय में कर सकते हैं।

156-मांगरोल विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक मामलतदार कार्यालय, मीटिंग हाल, मांगरोल तथा ग्राउंड फलोर मामलतदार कार्यालय मांगरोल में निर्धारित समय के दौरान कर सकते हैं।

157-मांडवी विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक मामलतदार कार्यालय मांडवी में, 158-कामरेज विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक कामरेज प्रांत अधिकारी कार्यालय, तालुका सेवा सदन, कामरेज में, 158-कामरेज विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक कामरेज प्रांत अधिकारी कार्यालय, तालुका सेवा सदन तथा मामलतदार कार्यालय में, 159-सूरत पूर्व विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक सी ब्लाक, बहुमाली भवन, नानपुरा, सूरत में, 160-सूरत विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक ए-ब्लाक, पांचवा माला, बहुमाली भवन, नानपुरा, सूरत में, 161-वराछा रोड विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक बी-ब्लाक, तीसरा माला, आपूर्ति विभाग, जिला सेवा सदन -2, सूरत में। 162-करंज विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक प्रांत अधिकारी कार्यालय, ओ-ब्लाक, तीसरा माला, जिला सेवा सदन-2, अठवालाइंस, सूरत में। 163-लिंबायत विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक प्रादेशिक तालीम केंद्र, गुजरात गैस सर्कल के पीछे, अडाजन, सूरत में। 164-उधना विधानसभा क्षेत्र के लि उमीदवारी पत्रक मामलतदार कार्यालय, सूरत शहर अठवालाइंस सूरत में। 165-मजूरा विधानसभा क्षेत्र के लिए उमीदवारी पत्रक बी-ब्लाक, चौथा माला, जिला सेवा सदन, अठवा लाइंस सूरत, में। 166-कतारगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उमीदवारी पत्रक पुरानी कलक्टर कार्यालय, बहुमाली भवन, नानपुरा, सूरत में। 167-सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए उमीदवारी पत्रक, जीआईडीसी कार्यालय, डच गार्डेन के सामने, नानपुरा, सूरत में। 168-चौर्यासी विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक मामलतदार कार्यालय, ए-ब्लाक, दूलरा माला, जिला सेवासदन-2, अठवालाइंस, सूरत में।

169-बारडोली विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक बारडोली प्रांत अधिकारी कार्यालय बारडोली तथा मामलतदार कार्यालय बारडोली में। 170-महुआ विधानसभा के लिए उमीदवारी पत्रक मामलतदार कार्यालय तालुका सेवा सदन, महुआ में किया जा सकता है।

केमिकल फेक्ट्री को कर्मचारियों ने लगाया 24.56 लाख का चूना

सूरत। पर्वत पाटिया के ग्रीन पार्क सोसायटी निवासी एक व्यापारी को उनके ही दो कामदारों ने 24 लाख 56 हजार की चटप लगादी होने का मामला सामने आया है। पुनागाव पुलिस के अनुसार राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी तथा ग्रीन पार्क सोसायटी निवासी मनोज भाई भवरलालजी लखेरा 41 व्यापारी है । पर्वत पटिया स्थित महावीर टेक्स्टाइल मार्केट में मनोज भाई की रितु कलर फ्रेम प्राइवेट लिमिटेड के नामसे केमिकल का व्यापार करते है । इस केमिकल फेक्ट्री में लिम्बायत के गोडादरा स्थित वृजधाम सोसायटी निवासी सुनील मोहनलाल सावलोट तथा पर्वत पटिया स्थित अभिषेक रेशिडेंसी निवासी कैलाश रामलाल लखारा नामक दोनो युवक नॉकरी करते थे । दोनो ठगों ने कंपनी द्वारा सप्लाई किये गए केमिकल के बिलों के साथ छेड़छाड़ कर तथा ट्रांसपोर्ट गोदाम से केमिकल अन्य व्यक्ति को बेच कर कंपनी को 24 लाख 56 हजार का चूना लगा कर फरार हो गए हादसे के चलते दोनो पीड़ितों की शिकायत पर पुनागाव पुलिस ने दोनो कामदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है ।

डिंडोली से कार चुराकर भाग ने वाले बदमाशोने कार छोड़कर फरार

सूरत। डिंडोली के बजरंग नगर सोसायटी के एक मकान को अनजान चोर उचकको ने निशाना बनाकर धर में प्रवेश कर कार की चाबी कराकर कार की चोरी करने की कोशिश की होने का मामला सामने आया है । कार चुराकर भाग रहे बदमाशोने कार को पीड़ित के धर के पास के गेट के साथ भिडन्त कर 1 लाख का नुकसान पहुचाया है । पुलिस सूत्रों के अनुसार डिंडोली के बजरंग नगर सोसायटी निवासी अरुण भाई ओमकारनाथ तिवारी 34 दलाल है । अरुण भाई ने अपनी कार धर के पास पार्क कर रख्खी थी । रात्रि दौरान दो अनजान चोर उचकको ने पीड़ित के धर को निशाना बना कर धर में प्रवेश किया था । और धर मेसे चाबी चुराकर कार लेकर भाग रहे थे इसी दौरान पीड़ित की नजर कार चोरो पर पड़ी थी और उन्हों ने चोर चोर की गुहार लागाने पर बदमाश भाग ने के चक्कर मे कार सोसायटी के डिवाइडर के साथ भिडन्त कर मोके पर कार छोड़ कर फरार हो गए । हादसे के चलते डिंडोली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरी और कार को 1 लाख का नुकसान पहुचाया होने का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है ।

कतारगाव की विवाहिता के साथ दुष्कर्म

सूरत। कतारगाव की एक विवाहिता को सोशियल मिडिया के फेसबुक पर बरोडा के युवक के साथ मित्र करना मंहगा पड गया । आरोपी युवक मुशलिम होने के बाद भी हिन्दू युवक का नाम धारण कर विवाहिता को अपने जाल में फास कर उसके साथ बरा बार जबरन दुष्कर्म किया होने का मामला सामने आया है । इतना ही नहीं आरोपी ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म दौरान लिए फ़ोटो व वीडियो लेकर उन्हें ब्लेकमेल कर जानसे खत्म करने की धमकी दी है । उमरा पुलिस के अनुसार बरोडा के तरसाडी निवासी इमरान उफ समीर समशेर चौहान नामक युवक नव सोशियल मीडिया के फेसबुक पर अपनी समीर चौहान ने नामसे एकाउन्ट बनाया था । उसके बाद कतारगाव निवासी विवाहिता के साथ फेसबुक पर मित्र बनाई थी । दोनो की मित्रता इस कदर बढ़ती गई कि दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन नबर भी दे दिया था और एक दुसरो के साथ बाते करना शरू कर दिया ।

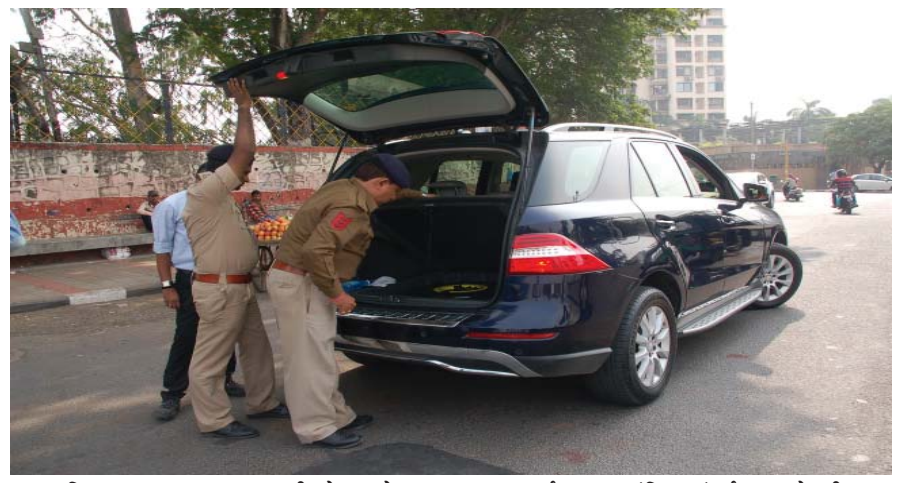

सूरत। विधान सभा आम चुनाव की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता अंतर्गत वाहनो की जांच की जा रही है। जिसके तहत मंगलवार को शहर के विविध मार्गो पर अधिकारियों द्वारा वाहनों की जांच की गई।

जीएसटी बेहतर लेकिन गलत तरीके से लागू की गई : यशवंतसिंहा

अहमदाबाद (ईएमएस)। लोकशाही बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ के आमंत्रण पर गुजरात में चुनावी माहौल के बीच अहमदाबाद आए यशवंत सिन्हा ने कहा कि जीएसटी एक बेहतर कर प्रणाली है पर इसे गलत तरीके से लागू किया गया है। अरूण जेटली इसमें सभी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं और इसके जरिए उन्होंने देश पर एक बहुत ही गलत ढंग वाली कर प्रणाली थोप दी है और अब इसमें अस्थाई अथवा तदर्थ अंदाज में बदलाव की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में देश और देश की जनता को उनको पद से हटाने की मांग करने का पूरा हक है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मौजूदा वित्त मंत्री अरूण जेटली को वह गुजरात पर 'बोझ' मानते हैं और जीएसटी को लागू करने में गड़बड़ी और इसके लिए उन्हें पद से इस्तीफे की जनता की मांग जायज है। हालांकि देश में कारोबारी सुगमता यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की स्थिति में सुधार का यशवंतसिंहा ने स्वागत किया और कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है पर मुश्किल यह है कि देश के बाहर की वाहवाही को स्वीकार करने वाले हम लोग देश के अंदर से होने वाली आलोचना को खारिज कर देते हैं। जबकि जरूरी यह है कि हमे इस बात की अधिक चिंता करनी चाहिए कि दुनिया की तुलना में भारत के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत कहा कि गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गये अरूण जेटली राज्य की जनता के लिए बोझ जैसे हैं। उन्होंने जेटली के खिलाफ सख्त तेवर अपनाते हुए कहा, 'मैं वित्त मंत्री को गुजराती नहीं मानता। वह गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए होंगे पर वे आप पर बोझ हैं। अगर वह नहीं चुने जाते तो उनकी जगह किसी गुजराती को मौका मिला होता। यशवंत सिन्हा ने जीएसटी के मौजूदा स्वरूप में बदलाव के लिए कई सुझाव भी दिए। एक प्रश्न के उत्तर में सिन्हा ने यह भी स्वीकार किया कि मोदी के गुजरात सीएम रहते जीएसटी का विरोध किया था और राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री सौरभ पटेल का यह बयान कि इससे गुजरात को नौ हजार करोड का नुकसान होगा अब भी संसदीय कार्यवाही की रिकार्ड में है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यव-स्था को नुकसान पहुंचाया है और अराजकता जैसी स्थिति पैदा की।

दुर्घटना देखने गए 3 युवक दुर्घटना का शिकार, तीनों की मौत

मेहसाणा (ईएमएस)। जिले के विसनगर-खेरालु रोड पर पालडी गांव के निकट हुई दुर्घटना को देखने गए बाइक सवार तीन युवकों की कार के चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेहसाणा जिले में विसनगर-खेलालु रोड पर पालडी गांव के निकट एक जीप सकर्ल से नीचे उतर गई थी। उस दौरान वहां से मोटर साइकिल पर गुजर रहे तीन युवकों ने बाइक खड़ी की और दुर्घटना स्थल की ओर जा रहे थे। उसी वक्त वहां से गुजरी एक तेज रफ्तार कार ने तीनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। कार की चपेट में आए तीनों की युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

कांग्रेस का राज्यभर में डोर टू डोर संपर्क अभियान शुरू

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने आज से राज्यभर में डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के नारणपुरा क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी और गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत ने अभियान का प्रारंभ किया। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी का गुजरात दौरा जाया नहीं होगा। चुनाव में जीत के विश्वास के साथ कांग्रेस से आज से राज्यभर में डोर टू डोर प्रचार अभियान शुरू कर दिया। अहमदाबाद के नारणपुरा निर्वाचन क्षेत्र के सोला रोड बस

स्टैन्ड के निकट स्थित कांकरिया हनुमान मंदिर से कांग्रेस ने अपने अभियान का श्रीगणेश किया। गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी ने कांग्रेस के डोर टू डोर प्रचार का प्रारंभ कराया। इसी प्रकार राज्यभर में कांग्रेस के प्रदेश नेता, सहप्रभारियों ने शहर-जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस का दावा है कि टीम कांग्रेस इस अभियान के तहत गुजरात के एक करोड़ घरों तक पहुंचेगी और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेगी। गौरतलब है नारणपुरा निर्वाचन क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ से डोर टू डोर प्रचार अभियान का प्रारंभ किया है।

अहमदाबाद की दस बस्तियों में बनाया क्रास का निशान, दहशत में बाशिंदे

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात के अहमदाबाद शहर के पाल्दी इलाके में लोग इन दिनों बहुत डरे हुए हैं। यहां की दस मुस्लिम सोसायटियों और हिंदू कॉलोनियों में लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस इलाके में कुछ दिन पहले ही एक विवादास्पद पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यह इलाका 'मुस्लिम बस्ती हो गया है। पोस्टर से सन 2002 में दंगों की विभिषिका झेल चुके डिलाइट अपार्टमेंट्स के लोग चिंतित हो उठे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि निशान लगाने का उद्देश्य मुस्लिम इलाकों की पहचान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य इलाके में अशांति फैलाना है। लाल रंग के निशान अमन कॉलोनी, नशेमन अपार्टमेंट, टैगोर फ्लैट, आशियाना अपार्टमेंट और तक्षशिला कॉलोनी के बाहर मेन गेट पर लगाए गए हैं। डिलाइट में रहने वाले आदिल बगादिया ने कहा, 'हमने चुनाव आयोग और पुलिस कमिश्नर से इलाके में शांति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तीन दिन पहले ही इस इलाके में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था, 'पलदी को जुहापुरा बनने से बचाइए।' बता दें, जुहापुरा भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम बस्तियों में से एक है। डिलाइट अपार्टमेंट के वॉचमैन सत्तार चुनार ने कहा उन्होंने लाल निशान पर काला स्प्रे छिड़क दिया है। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने बताया कि जिन इलाकों से कूड़ा उठाना है, उनकी पहचान के लिए सफाई कर्मचारियों ने ये निशान लगाए हैं। उधर, अमन कॉलोनी के जुबेर अहमद ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें नगर निगम से यह नहीं बताया गया है कि ये निशान कूड़ा उठाने के लिए हैं। उधर, नगर निगम के अधिकारियों के बयान ने भी भ्रम पैदा किया है।

भाजपा ने जारी किया नया प्रचार वीडियो

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस लोगों को खासकर युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रही हैं। इसके अंतर्गत भाजपा और कांग्रेस के एक के बाद एक प्रचार वीडियो जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा ने नया प्रचार वीडियो जारी किया है। जिसमें हिन्दी-गुजराती मशहूर फिल्म अभिनेत मनोज जोशी भाजपा की उपलब्धियों का बखान और कांग्रेस खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस के युवराज की कोमेडी के अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी और उनकी खाम नीति पर टिप्पणी की गई है। वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस वषी से जातिवाद की राजनीति कर देश को तोड़ने प्रयास कर रही है और माधवसिंह खाम नीति से गुजरात के लोगों को दूर किया। इतना ही नहीं ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का ईना-मीना-डीका नाम देकर उन पर भी आरोप लगाए गए हैं।

एक फोटो में केंद्रीय मंत्री के साथ दिखा अश्विन

बीजेपी बोली, सीडी से हमारा कोई लेना-देना नहीं

अश्विन ने ही जारी की है हार्दिक पटेल की सीडी

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात चुनाव में एक सीडी से हंगामा मच गया है। बीजेपी इस सीडी में हार्दिक पटेल के होने का दावा कर रही है, जबकि हार्दिक पटेल सीडी को फर्जी बताते हुए इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ सीडी जारी करने वाले शख्स की तस्वीर सामने आने से विवाद और गहरा गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है। बीजेपी के मंत्री के साथ अश्विन (सीडी जारी करने वाले) की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया ने साफ किया कि पूरे प्रकरण से बीजेपी का लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। गुजरात चुनाव में वीडियो वॉर के बाद अब सीडी पर संग्राम शुरू हो गया है। यू-ट्यूब पर वायरल इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बताया जा रहा है। सीडी पर हंगामा बढ़ने के बाद इसे जारी करने वाले अश्विन सांकड़सरिया नाम के शख्स सामने आया और दावा किया कि उसके पास हार्दिक पटेल के कई साथियों की भी सीडी है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) **E-mail: krantisamay@gmail.com**